



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1104]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 6, 2016/वैशाख 16, 1938

No. 1104]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 6, 2016/ VAISAKHA 16, 1938

विदेश मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 5 मई, 2016

का.आ. 1669(अ).—संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 7 के अधीन अपनी 7396वीं बैठक में संकल्प 2206(2015) (इस आदेश के साथ संलग्न) अंगीकार किया जिसके द्वारा सभी राज्यों से ऐसे उपाय करने की अपेक्षा की गई कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके नागरिकों, व्यक्ति को या उनके भू-क्षेत्र में स्थित इकाइयों द्वारा निधियां, वित्तीय आस्तियां या आर्थिक संसाधन, उक्त संकल्प द्वारा स्थापित समिति द्वारा नामित व्यक्तियों या इकाइयों को अथवा उनके फायदे के लिए न दिए जाएं और अभिहित व्यक्तियों को अपने भू-क्षेत्र में प्रवेश या वहां से पारगमन से रोकें;

और केंद्रीय सरकार यह आवश्यक और समीचीन विचार करती है कि दक्षिण सूडान में समावेशी तथा दीर्घकालिक शांति की खोज का समर्थन करने के लिए संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 7 के अधीन अंगीकृत सुरक्षा परिषद के उक्त संकल्प को कार्यान्वित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र (सुरक्षा परिषद) अधिनियम, 1947 (1947 का 43) के अधीन आदेश जारी किया जाए;

अतः अब संयुक्त राष्ट्र (सुरक्षा परिषद) अधिनियम, 1947 (1947 का 43) की धारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार एतद्वारा उपरोक्त संकल्प को प्रभावी रूप देने के लिए निम्नलिखित आदेश देती है, अर्थातः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम दक्षिण सूडान संबंधी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प का कार्यान्वयन आदेश, 2016 है।

(2) यह भारत के राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषाएं- (1) इस आदेश में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो-

(क) "समिति से अभिप्रेत है जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा संकल्प 2206(2015) के पैरा 16 के अनुरूप स्थापित प्रतिबंध समिति से होगा।

(ख) "संकल्प से अभिप्रेत है जो 03 मार्च, 2015 को अंगीकृत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का संकल्प 2206(2015) होगा और इसमें दक्षिण सूडान संबंधी संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अध्याय 7 के अंतर्गत सुरक्षा परिषद द्वारा अंगीकृत संकल्प 2057(2012), 2109(2013), 2132(2013), 2155(2014) और 2187(2014) शामिल हैं।

(ग) "अनुसूची" से अभिप्रेत है, उनके उक्त संकल्पों में सुरक्षा परिषद द्वारा किए गए अवधारण के आधार पर तैयार इस आदेश के साथ संलग्न अनुसूची से है।

(2) इस आदेश में उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किंतु का आशय वही रहेगा जो उस समय प्रवृत्त ऐसी विधियों में क्रमशः समनुदेशित किया गया है।

3. आदेश की प्रयोज्यता- समय-समय पर संशोधित इस आदेश के उपाबंध उक्त संकल्पों तथा अनुसूची के दायरे में आने वाले व्यक्तियों तथा इकाइयों पर लागू होंगे।

4. संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार की शक्तियां- केंद्रीय सरकार के पास निम्नलिखित उपायों के लिए सभी शक्तियां होंगी,

(क) अपने भू-क्षेत्र में, समिति द्वारा अभिहित किसी व्यक्ति अथवा इकाई द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से, स्वामित्व में या नियंत्रित अथवा उनकी ओर से अथवा उनके निदेश पर कार्य कर रहे व्यक्तियों या इकाइयों द्वारा अथवा उनके स्वामित्व में या नियंत्रित इकाइयों द्वारा धारित सभी निधियों, अन्य वित्तीय आस्तियों अथवा आर्थिक संसाधनों पर बिना विलंब रोक लगाना;

(ख) यह सुनिश्चित करना कि खंड (क) में विनिर्दिष्ट न तो ये और न ही कोई अन्य विधियां वित्तीय परिसंपत्तियां अथवा आर्थिक संसाधन और न ही कोई अन्य निधियां, वित्तीय परिसंपत्तियां अथवा आर्थिक संसाधन, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, उनके नागरिकों अथवा उनके भू-क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों द्वारा उपलब्ध कराई जाए, परंतु निम्नलिखित मामलों को छोड़ दिया जाएगा;

- (i) मूल खर्च;
- (ii) असाधारण खर्च; और
- (iii) न्यायिक, प्रशासनिक अथवा विवाचन धारणाधिकार अथवा न्यायिक निर्णय से संबंधित खर्च,

संकल्प 2206(2015) के पैरा 13 और पैरा 14 और 15 में विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं के अधीन, जैसा भी इस मामले में लागू हो;

(ग) यात्रा अथवा प्रवेश अथवा पारगमन में छूट के उपाबंध के साथ निर्दिष्ट व्यक्तियों की अपने भू-क्षेत्रों में प्रवेश अथवा पारगमन पर रोक लगाना;

- (i) समिति द्वारा मामला दर मामला आधार पर निर्धारित धार्मिक बाध्यता सहित, मानवीय आवश्यकताओं के आधार पर न्यायोचित है,
- (ii) न्यायिक प्रक्रिया की पूर्ति के लिए; और
- (iii) समिति द्वारा यथावधारित मामला दर मामला आधार पर दक्षिण सूडान में शांति और राष्ट्रीय सुलह के उद्देश्यों को आगे बढ़ाना;

संकल्प 2206(2015) के पैरा 11 में उल्लिखित प्रक्रियाओं के अधीन, जैसा कि इस आसन्न मामले में लागू हो।

अनुसूची

(पैरा 2(ख) देखें)

इस अनुसूची में निम्नलिखित सम्मिलित हैं, अर्थात:-

- i. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा 03 मार्च, 2015 को अंगीकृत यूएनएससी संकल्प 2206(2015) का पाठ;
- ii. 2206 समिति द्वारा स्थापित तथा अनुरक्षण सूची।

I. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प एस/आरईएस/2206(2015)

सुरक्षा परिषद द्वारा 03 मार्च, 2015 को अपनी 7396वीं बैठक में अंगीकृत।

सुरक्षा परिषद:

दक्षिण सूडान के संबंध में अपने पिछले संकल्पों और वक्तव्यों, विशिष्टया संकल्प 2057(2012), 2109(2013), 2132(2013), 2155(2014) और 2187(2014) का स्मरण करते हुए,

दिसम्बर, 2013 से दक्षिण सूडान गणराज्य की सरकार तथा विपक्षी दलों के बीच संघर्ष जो देश राजनैतिक तथा मिलिट्री लीडर्स के बीच आंतरिक राजनैतिक विवादों से उत्पन्न हुआ, के संबंध में जबरदस्त चेतावनी और चिंता व्यक्त करते हुए,

इस बात से अत्यधिक चिंतित होकर कि इस संघर्ष से अत्यधिक मानवीय विपत्तियां उत्पन्न हुई हैं जिनमें अत्यधिक हानि हुई, दो मिलियन लोगों का विस्थापन हुआ और संपत्ति का नुकसान हुआ तथा दक्षिण सूडान के लोगों के बीच दरिद्रता आई और उनको हानि हुई,

सभी पक्षों द्वारा अतीत में हुई तथा इस समय चल रही मानवाधिकार उल्लंघनों तथा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के दुरुपयोग तथा उल्लंघनों की कड़ी निंदा करते हुए और सशस्त्र समूहों तथा राष्ट्रीय सुरक्षा बलों सहित तथा ऐसे दुरुपयोग एवं उल्लंघन करने के लिए उकसाने सहित सिविलियनों की लक्षित हत्याओं, जातीय लक्षित हिंसा, न्यायोत्तर हत्याओं, बलात्संग तथा यौन और लिंग आधारित हिंसा के अन्य प्रकारों, सशस्त्र संघर्ष में बच्चों की भर्ती और उपयोग, अपहरण, जबरदस्ती गायब कर देने, स्वेच्छाचारी गिरफ्तारियों और नजरबंदियों, सिविलियन लोगों के बीच आतंक फैलाने के उद्देश्य से हिंसा तथा विद्यालयों, उपासना स्थलों और अस्पतालों, संयुक्त राष्ट्र और संबद्ध शांतिरक्षक कार्मिकों तथा पदार्थों पर हमलों की *जबरदस्त निंदा करते हुए*, सिविल सोसाइटी, मानवाधिकार कार्मिकों और पत्रकारों को प्रताड़ित और लक्षित करने की *भी निंदा करते हुए*, और इस बात पर *बल देते हुए* कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों के उल्लंघनों और दुरुपयोगों के जिम्मेवार लोगों को उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए तथा दक्षिण सूडान की सरकार अपने नागरिकों को जातिसंहार, युद्ध अपराधों, जातीय सफाए और मानवता के विरुद्ध अपराधों से सुरक्षित रखने की मौलिक जिम्मेदारी ले,

व्यक्तियों के बड़े पैमाने पर विस्थापन और मानवीय संकट के गहराने पर *गहन चिंता व्यक्त करते हुए*, दक्षिण सूडान के लोगों की मुसीबतों के लिए संघर्ष से संबद्ध सभी पक्षों द्वारा दायित्व लेने और इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि लोगों की मौलिक आवश्यकताएँ पूरी की जाएँ, और *बल देते हुए*, नागरिकों को तात्कालिक तथा समन्वित सहायता प्रदान करने में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार अभिकरणों एवं उनके भागीदारों की *प्रशंसा करते हुए*, सभी जरूरतमंद लोगों को तथा विशेष रूप से आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों एवं शरणार्थियों को, अंतर्राष्ट्रीय विधि और मानवाधिकार सहायता के संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार, राहत कार्मिकों, उपकरण तथा आपूर्तियों तक पूर्ण, सुरक्षित तथा निर्बाध पहुंच की सहायता उपलब्ध कराने हेतु संघर्ष से जुड़े सभी पक्षों का *आह्वान करते*, मानवाधिकार कार्मिकों तथा सुविधाओं के विरुद्ध हमलों की *निंदा करते हुए* और यह स्मरण करते हुए कि मानवाधिकार कार्मिकों के विरुद्ध हमले तथा नागरिकों के अस्तित्व के लिए अपरिहार्य सामग्री से उन्हें वंचित करने को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार विधि का उल्लंघन माना जाएगा,

राजनैतिक और सुरक्षा वार्ता के लिए एक मंच स्थापित करने में विकास संबंधी अंतरसरकारी प्राधिकरण (आईजीएडी) मंत्रिसमूह की पहल, जिसका संयुक्त राष्ट्र तथा अफ्रीकी संघ ने समर्थन किया, की *प्रशंसा करते हुए*, और सभी पक्षों ने इस प्रक्रिया में सहभागिता करने तथा राष्ट्र/शासनाध्यक्षों की आईजीएडी सभा द्वारा 13 मार्च, 2014 को लिए गए निर्णयों का सम्मान करने की *इच्छा करते हुए*,

दक्षिण सूडान के संकट के समाधान के लिए की गई आईजीएडी की मध्यस्थता वाली वचनबद्धताओं, नामतः शत्रुता समाप्त करने संबंधी 23 जनवरी, 2014 के करार, दक्षिण सूडान के संकट के समाधान संबंधी 9 मई, 2014 के करार; और दक्षिण सूडान गणराज्य में राष्ट्रीय एकता की परिवर्ती सरकार (टीजीओएनयू) की स्थापना संबंधी 1 फरवरी, 2015 के करार का *स्वागत करते हुए*,

राष्ट्रध्यक्षों की आईजीएडी सभा में उल्लिखित संकल्प तथा 10 जनवरी, 2014 और 25 अगस्त, 2014 की सरकारी विज्ञप्ति का *स्वागत करते हुए* कि आई जी ए डी सदस्य राष्ट्र इस बात के लिए और आगे मिलकर कार्रवाई करेंगे कि जो पक्ष इस तारीख के संबंध में

अपनी वचनबद्धताओं को पूरा करने में अथवा उस सभा की विज्ञप्ति के प्रतिकूल कार्य करता है, उस पर दबाव डाला जाएगा जिसमें दंडात्मक उपायों के माध्यम से भी कार्य किया जाना शामिल है,

अफ्रीकी संघ शांति और सुरक्षा परिषद (एयूपीएससी) के 12 जून, 2014 की विज्ञप्ति का स्वागत करते हुए, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ इस बात पर बल दिया गया है कि आईजीएडी की अनुशंसा पर परिषद ऐसे किसी भी पक्षकार के विरुद्ध तत्काल प्रतिबंध लगाने व अन्य उपायों के लिए तैयार रहेगी जो संघर्ष के समाधान के लिए प्रयास करने के आदेश को मानने से इंकार करता है और अपनी वचनबद्धताओं को पूरा करने में असफल रहता है,

एयूपीएससी की 17 सितम्बर, 2014 की उस विज्ञप्ति का भी *स्वागत करते हुए* जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ इस पर बल दिया गया है कि आईजीएडी के साथ समन्वय से इसके द्वारा यह संकल्प लिया गया कि जो कोई भी पक्ष अपनी वचनबद्धताओं को पूरा करने में असफल रहता है और विद्यमान संकट का बातचीत के माध्यम से समाधान के लिए प्रयास करने के आदेशों की लगातार अवहेलना करता है, उसके विरुद्ध आवश्यक उपाय किए जाएंगे।

10 जून, 2014 की 26वीं विज्ञप्ति में निर्धारित 60 दिन की अवधि के भीतर एक संक्रमणकालीन सरकार के गठन हेतु करार संपन्न करने में असफल रहने के लिए दक्षिण सूडान गणराज्य की सरकार तथा विरोधी पक्ष सूडान पीपुल्स लिबरेशन मूवमेंट (एसपीएलएम) की जोरदार भर्त्सना करते हुए,

25 अगस्त, 2014 को अदिस अबाबा में राष्ट्राध्यक्ष तथा सरकार की आईजीएडी सभा के 27वें असाधारण सत्र की विज्ञप्ति का ध्यान लेते हुए, जिसमें अन्य बातों के साथ: आज की स्थिति के अनुसार पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित अधिकांश करारों के उल्लंघनों की निंदा की गई, वार्ताओं के लिए एक समग्र तथा विस्तृत आधार वाले दृष्टिकोण की आवश्यकता दोहराई, दक्षिण सूडान में बिगड़ती मानवीय स्थिति गंभीर चिंता व्यक्त की और 45 दिन के भीतर राष्ट्रीय एकता की संक्रमणकालीन सरकार के बारे में बातचीत करके करार निष्पादन करने के लिए सभी हित धारकों का आह्वान किया;

7 नवंबर, 2015 को अदिस अबाबा में राष्ट्राध्यक्षों तथा सरकारों के आईजीएडी सभा के 28वें असाधारण सत्र की विज्ञप्ति का ध्यान रखते हुए, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह संकल्प लिया गया कि दक्षिणी सूडान की सरकार और विपक्षी ताकतें बिना शर्त, पूर्णतः तथा तत्काल सभी शत्रुतापूर्ण कार्रवाई समाप्त करने का वचन दे: क्षेत्र के भीतर परिसंपत्ति जब्त करने तथा यात्रा पर प्रतिषेध लागू करने के लिए आईजीएडी क्षेत्र के राष्ट्रों द्वारा मिलकर कार्रवाई का आमंत्रण दिया और दक्षिण सूडान की सरकार तथा विपक्षी ताकतें यदि शत्रुतापूर्ण कार्रवाई पर लगे प्रतिबंध का किसी प्रकार का कोई उल्लंघन करती है तो युद्ध में उपयोग में लाए जा सकने वाले शस्त्र तथा किसी अन्य सामग्री की आपूर्ति से इंकार किया और इन उपायों के कार्यान्वयन में इन्हें लागू करना आवश्यक हो तो उन्हें हर संभव सहायता देने के लिए एयूपीएससी, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद तथा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का आह्वान किया;

तंजानिया संयुक्त गणराज्य की सरकार के तत्वाधान में सम्मत एसपीएलएम के एकीकरण पर 21 जनवरी, 2015 के करार और आरुशा एसएलपीएम एकीकरण करार के चरण-1 के कार्यान्वयन पर एसपीएलएम त्रिपक्षीय समिति की बैठक की 16 फरवरी, 2015 की विज्ञप्ति का संज्ञान लेते हुए,

5 दिसंबर, 2014 और 29 जनवरी, 2015 के एयूपीएससी विज्ञप्तियों का संज्ञान लेते हुए जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ इस बात पर जोर दिया गया कि उन सभी पक्षकारों के विरुद्ध प्रतिबंध लगाया जाएगा जो राजनीतिक प्रक्रिया में बाधा डालते हैं और 23 जनवरी, 2014 के शत्रुतापूर्ण कार्रवाई पर रोक, संबंधी करार को कमजोर बनाते हैं। खातूम में 12 जनवरी, को आयोजित आईजीएडी के नेतृत्व में दक्षिण सूडान शांति प्रक्रिया के समर्थन में विशेष परामर्श के दौरान जी आरएसएस तथा विपक्षी दल (एसपीएलएम/ए) इन विपक्ष के प्रतिनिधियों द्वारा सहमत चीन की मध्यस्थता वाले पांच सूत्री योजना का स्वागत करते हुए; नामतः (i) सभी हस्ताक्षरित करारों के ईमानदारी से पूर्ण कार्यान्वयन हेतु वचनबद्धता (ii) यथाशीघ्र एक संक्रमणकालीन सरकार के गठन के लिए वार्ता की गति बढ़ाना (iii) संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में मानवीय स्थिति बहाल करने हेतु ठोस कदम उठाना और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय सहायता की उपलब्धता को सुगम बनाना (iv) दक्षिण सूडान में कार्यरत सभी देशों तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठानों के सभी कार्मिकों तथा संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और (v) आईजीएडी के नेतृत्व वाले मध्यस्थता संबंधी प्रयासों में सक्रिय रूप से भाग लेने तथा दृढ़ समर्थन प्रदान करना और इस संबंध में, दोनों पक्षकारों को पंचवर्षीय योजना के तत्काल कार्यान्वयन हेतु पुरजोर आग्रह करते हुए,

दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन, शांति सैनिक तथा सैन्य टुकड़ी एवं पुलिसकर्मी योगदानकर्ता राष्ट्रों द्वारा राष्ट्रों जिनमें विदेशी नागरिक शामिल हैं, को शारीरिक हिंसा तथा सुरक्षा स्थिति को बिगाड़ने की कोशिशों से बचाने में की गई कार्रवाई की भूरिभूर सराहना करते हुए;

21 फरवरी, 2014 के "यूएनआईएमएसएस "अंतरिम मानवाधिकार रिपोर्ट" और 8 मई, 2014 का यूएनआईएमएसएस " दक्षिण सूडान में संघर्ष : एक मानवाधिकार रिपोर्ट" और 19 दिसंबर के यूएनआईएमएसएस " विशेष रिपोर्ट : बेन्तियू संयुक्त राष्ट्र पर आक्रमण" और 9 जनवरी, 2015 यूएनआईएमएसएस रिपोर्ट "बेन्तियू तथा दोर में नागरिकों पर आक्रमण" पर रूचिपूर्ण ध्यान रखते हुए;

इस बात पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कि यूएनएमआईएसएस 8 मई, 2014 "दक्षिण सूडान में संघर्ष: एक मानवाधिकार रिपोर्ट" के अनुसार, यह विश्वास करने के युक्तियुक्त कारण हैं कि मानवता के विरुद्ध अपराध जिसमें न्यायालयों से बाहर हत्या, बलात्संग तथा यौन हिंसा के अन्य कार्य जबरन लापता और मनमानी कार्रवाई शामिल है, सरकार तथा विपक्षी ताकतों दोनों द्वारा की गई है और यह कि युद्ध अपराध किए गए हैं और दक्षिण सूडान में दंड-मुक्ति की समाप्ति की अनिवार्य और तत्काल आवश्यकता पर बल देते हुए तथा ऐसे अपराधियों को सजा देने के लिए,

एक संक्रमणकालिक एजेंडे के प्रमुख तत्व के रूप में अंतर्राष्ट्रीय जांचों की महत्वपूर्ण भूमिका का ध्यान रखते समय जिम्मेदारी, मेल-मिलाप तथा सांत्वना पर जोर देते हुए और जहां समुचित हो, युद्ध अपराधों तथा मानवता के विरुद्ध अपराधों में संलिप्त लोगों को जिम्मेदार ठहराने के संबंध में अभियोजित पक्ष महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं;

जांच पड़ताल तथा उल्लंघनों के प्रलेखन और साथ ही दक्षिण सूडान में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय विधि के उल्लंघन से संबंधित अफ्रीकी संघ जांच आयोग के कार्यों को स्वीकार करते हुए, इसके निष्कर्षों तथा सिफारिशों के बारे में रुचिकर तरीके से अनुमान लगाते हुए, इसकी अंतिम रिपोर्ट को यथाशीघ्र सार्वजनिक रूप से जारी किए जाने को प्रोत्साहित करते हुए और दक्षिण सूडान हेतु न्याय और उत्तरदायित्व और साथ ही राहत एवं आपसी मेल-मिलाप सुनिश्चित करने हेतु अफ्रीकी संघ के विनियोजन का स्वागत करते हुए,

किसी जातिगत समूह विशेष के विरुद्ध यौन उत्पीड़न को भड़काने वाले घृणापूर्ण भाषण और संदेश प्रसारित करने हेतु मीडिया के उपयोग की सख्त भर्त्सना करते हुए जिससे बड़े पैमाने पर हिंसा तथा संघर्ष भड़काने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने की क्षमता हो और दक्षिण सूडान गणराज्य की सरकार का इस प्रकार के कार्यकलापों पर लगाम लगाने हेतु समुचित उपाय करने के लिए संबोधित करते हुए और आगे सभी दलों से यह आग्रह करते हुए कि वे ऐसी कार्रवाई से बाज आएँ और इसके बजाए समुदायों के बीच शांति एवं आपसी मेल-मिलाप को बढ़ावा देने में योगदान दें,

दक्षिण सूडान में सिविल सोसाइटी संगठनों, धर्म गुरुओं, स्त्रियों और युवाओं द्वारा अदा की गई महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए, देश में एक स्थाई समाधान तलाशने के लिए पूर्व एसपीएलएम बंधकों तथा अन्य राजनैतिक दलों के साथ-साथ उनकी भागीदारी के महत्व को समझते हुए और सरकार द्वारा ऐसी भागीदारी को सीमित रखने हेतु जिनमें वार्ता में शामिल होने जा रहे लोगों को रोकना तथा अपने विचारों को प्रकट करने की स्वतंत्रता पर अधिक से अधिक निर्बाधित लगाना शामिल है,

सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर चिंता व्यक्त करते हुए, स्त्रियों, शांति तथा सुरक्षा, बालकों और सशस्त्र संघर्ष और सशस्त्र संघर्ष से नागरिकों की सुरक्षा से संबंधित संगत संकल्पों और साथ ही मानवीय तथा संयुक्त राष्ट्र कर्मियों की सुरक्षा संबंधी संकल्प संख्या 1502 (2003), नरसंहार पर रोक तथा इसके विरुद्ध लड़ाई संबंधी संकल्प संख्या 2150 (2014) और सुरक्षा क्षेत्र में सुधार से संबंधित संकल्प संख्या 2151 (2014) की पुनः अभिपुष्टि करते हुए,

संकल्प संख्या 1209 (1998) और 2117 (2013) का स्मरण करते हुए और दक्षिण सूडान में अवैध स्थानांतरण अस्थिरताकारी जमावड़े तथा छोटे शस्त्रों और हल्के हथियारों के दुरुपयोग से शांति एवं सुरक्षा के लिए उत्पन्न खतरे पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए और इस प्रकार के हथियारों के अवैध परिचालन से निपटने के लिए प्रयासों को और मजबूत बनाने के महत्व पर बल देते हुए,

यूएनएमआईएसएस के आवाजाही तथा प्रचालनों पर लगाए गए निरंतर प्रतिबंधों पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए, संयुक्त राष्ट्र तथा आईजीएडी कर्मियों तथा सुविधाओं पर सरकार एवं विरोधी बलों तथा अन्य गुटों द्वारा किए जा रहे हमलों, संयुक्त राष्ट्र तथा संबंधित

कर्मियों को बंधक बनाए जाने तथा उनके अपहरण की सख्त निंदा करते हुए और दक्षिण सूडान की सरकार का इन हमलों की व्यापक रूप से त्वरित जांच करने और जिम्मेदार व्यक्तियों पर कार्रवाई करने के लिए आह्वान करते हुए,

यह निर्धारित करते हुए कि दक्षिण सूडान में व्याप्त परिस्थित उस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए धमकी है,

संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अध्याय-7 के अनुच्छेद-41 के तहत कार्रवाई करते हुए,

1. शत्रुताकार्य करार विराम ("सीओएच करार") का अनुसमर्थन जिसे दक्षिण सूडान गणराज्य की सरकार और विरोधी पक्ष एसपीएलएम द्वारा तारीख 23 जनवरी, 2014, 6 मई, 2014 तथा 9 मई, 2014 को स्वीकृत एवं इस पर हस्ताक्षरित किया गया;

2. अपनी तारीख को प्रतिबद्धताओं को पूरा ना कर पाने, इस संकट का कोई राजनैतिक समाधान तलाशने के लिए सार्थक तरीके से शांति प्रक्रिया को कार्यान्वित ना कर पाने के लिए गंभीर चिंता व्यक्त करता है और विशेष रूप से आईजीएडी अनुवीक्षण एवं जांच तंत्र द्वारा यथाप्रलेखित सीओएच करारों का निरंतर उल्लंघन किए जाने की निंदा करता है;

3. यह मांग करता है कि सभी दल सीओएच करारों की सभी पहलुओं का सम्मान करें और तत्काल 9 मई, 2014 को सम्पन्न करार तथा अन्य संगत करारों के अनुरूप आवश्यक तौर-तरीकों को लागू करें जिनमें 15 दिसम्बर, 2013 से दक्षिण सूडान में तैनात विदेशी सैनिकों को धीरे-धीरे हटाया जाना शामिल है, दक्षिण सूडान में सशस्त्र संघर्ष में संलग्न सभी पक्षों का आह्वान करता है कि वे अंतर्राष्ट्रीय मानवीय विधियों के सभी प्रकार के उल्लंघनों तथा मानवाधिकार उल्लंघनों एवं इसके दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए स्पष्ट आदेश जारी करें और इस आवश्यकता पर बल देते हुए कि सभी पक्ष यह सुनिश्चित करें कि मानवता से जुड़े अभिकरणों की सुविधा तत्काल सुलभ हो और आगे यह भी मांग करता है कि सभी पक्ष आगे और विलंब ना करते हुए एक व्यापक करार निष्पादित करने हेतु प्रतिबद्धता व्यक्त करें;

4. इस बात को पुनः दोहराया जाता है कि इस संघर्ष का कोई सैन्य समाधान नहीं है;

अनुशास्ति निर्देशित करने का मानदंड

5° दक्षिण सूडान में एक समावेशी एवं चिरस्थायी शांति हेतु समर्थन देने के लिए लक्षित अधिरोपित करने की इच्छा का उल्लेख करता है;

6° यह निर्णय लेता है कि पैरा-9 के उपबंध व्यष्टिकों और असितत्वों पर लागू होंगे और यह कि पैरा-12 के उपबंध व्यक्तियों तथा संगठनों पर लागू होंगे जैसा कि इस संकल्प के पैरा-16 के अनुसरण में ("समिति") क्रमशः पैरा-16 (ग) तथा 16 (घ) के अनुसरण में स्थापित समिति द्वारा इस प्रकार के उपाय निर्धारित किए गए हों, जो प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी संघर्ष में संलग्न रहने, ऐसी कार्रवाई अथवा नीतियों में शामिल रहने के लिए जिम्मेदार हो जिससे दक्षिण सूडान में शांति, सुरक्षा तथा स्थिरता को खतरा हो;

7° इस पर बल दिया गया है कि उपर्युक्त पैरा 6 में उल्लिखित कार्रवाईयों या नीतियों को शामिल किया जा सकता है परंतु ये इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:-

(क)° ऐसी कार्रवाई या नीतियां, जिनका मंतव्य या कार्य दक्षिण सूडान में संघर्ष को बढ़ाना या मेल-मिलाप या शांतिवार्ता में व्यवधान डालना तथा शत्रुता विराम करार का उल्लंघन करना हो;

(ख)° कार्रवाईयां या नीतियां जो परिवर्तनकालिक करारों के लिए खतरा है या दक्षिण सूडान में राजनीतिक प्रक्रिया को क्षति पहुंचाते हैं;

(ग)° ऐसे कार्यों की योजना बनाना, निर्देशन करना या ऐसे कृत्य करना जो प्रयोज्य अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार विधि या अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानूनों का उल्लंघन करते हों या दक्षिण सूडान में ऐसे कृत्य करना जिन्हें मानवाधिकारों का दुरुपयोग कहा जा सकता है;

(घ)° हिंसा के कृत्य (जिनमें जान से मार देना, अंग-भंग करना, यातना देना या बलात्संग करना या अन्य लैंगिक हिंसा शामिल है) अपहरण, जबरदस्ती उठा लेना, गायब करा देना, बलपूर्वक विस्थापन या विद्यालयों, अस्पतालों, धार्मिक स्थलों, जहां नागरिक शरण ले रहे हैं, पर हमलों के जरिए आम नागरिक, जिनमें महिलाएं और बच्चे शामिल हैं, को लक्ष्य बनाना या ऐसे कृत्य जो मानवाधिकारों के गंभीर दुरुपयोग या अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी विधियों के उल्लंघन से संबंधित हों;

- (ङ)° दक्षिण सूडान में सशस्त्र विवाद के परिप्रेक्ष्य में सशस्त्र समूहों या सशस्त्र बलों द्वारा बालकों की भरती या उपयोग;
- (च)° दक्षिण सूडान में अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापना, राजनयिक या मानवतावादी मिशनों के क्रिया-कलापों में व्यवधान तथा आईजीएडी की देख-रेख और सत्यापन प्रणाली या मानवतावादी सहायतार्थ या वितरण या उस तक पहुंच;
- (छ)° संयुक्त राष्ट्र मिशनों, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बलों या अन्य शांति स्थापक या मानवतावादी कार्मिकों के विरुद्ध हमले; या
- (ज)° समिति द्वारा अभिहित व्यष्टिक या निकाय की ओर से या उनके लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कार्य करना;
8. निर्णय किया गया है कि पैरा 9 और 12 के उपाबंध समिति द्वारा ऐसे कार्यों के लिए अभिहित उन व्यक्तियों पर लागू होंगे जो दक्षिण सूडानी सरकार सहित प्रतिपक्ष, रक्षक सैन्य या आतंकी समूह या किसी निकाय के नेता हैं या जिनके सदस्य उपर्युक्त पैरा 6 और 7 में वर्णित किसी भी क्रिया-कलापों में शामिल हैं;

यात्रा पाबंदी

9. निर्णय लिया गया है कि इस संकल्प के स्वीकार करने की तारीख से एक वर्ष की प्रारंभिक अवधि के लिए, सभी सदस्य राष्ट्र किन्हीं व्यष्टिकों, जिन्हें समिति द्वारा अभिहित किया गया है, को अपने भू-भागों में प्रवेश करने या पारगमन करने से रोकने के आवश्यक उपाय करेंगे, परंतु इस पैरा में कुछ भी ऐसा प्रावधान नहीं किया गया है जो किसी राष्ट्र को अपने क्षेत्र में अपने नागरिकों के प्रवेश से मना करने हेतु बाध्यकारी हो।
10. ध्यान किया गया है कि अभिहित व्यष्टिकों के पास बहुसंख्य राष्ट्रीयता या पासपोर्ट हो सकते हैं, चिंता प्रकट की गई है कि दो राष्ट्रों के बीच यात्रा जिसकी राष्ट्रीयता या पासपोर्ट नामोदिष्ट व्यक्ति के पास हो, पैरा 9 में लगाए गए यात्रा पाबंदी उद्देश्यों को बाधित करता है, और अनुरोध है कि इस संकल्प (विशेषज्ञों का पैनल) के पैरा 18 में उल्लिखित विशेषज्ञों का पैनल ऐसी यात्रा के बारे में समिति को रिपोर्ट करेगा।
11. निर्णय किया जाता है कि उपर्युक्त पैरा 9 में अधिरोपित उपाय लागू नहीं होंगे:
- (क)° जहां समिति मामला-दर-मामला आधार पर यह निर्णय करेगी कि ऐसी यात्रा मानवीय जरूरतों के आधार पर युक्तियुक्त है और इसमें धार्मिक बाध्यता शामिल है;
- (ख)° जहां प्रवेश करना या यात्रा न्यायिक प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आवश्यक है;
- (ग)° जहां समिति मामला-दर-मामला आधार पर यह अवधारित करती है कि इस छूट से दक्षिण सूडान में शांति और राष्ट्रीय मेल-मिलाप के उद्देश्यों की पूर्ति होगी और क्षेत्र में स्थायित्व आएगा।

आस्ति पर रोक लगाना (फ्रीज करना)

12. निर्णय किया गया है कि इस संकल्प के अंगीकार करने की तारीख से एक वर्ष की आरंभिक अवधि के लिए बिना किसी देरी के सभी सदस्य राष्ट्र अपने क्षेत्र में स्थित ऐसी सभी निधियों, वित्तीय आस्ति और आर्थिक संसाधनों को कीलित (संपत्ति के लेन-देन पर रोक) कर देंगे, जो समिति द्वारा नामोदिष्ट व्यक्तियों या निकायों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण या स्वामित्व में या उनकी ओर से या उनके निर्देश पर काम करने वाले अथवा उनके स्वामित्व या नियंत्रणाधान हों और यह भी निर्णय किया गया है कि सभी सदस्य राष्ट्र आरंभिक अवधि में यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके नागरिकों द्वारा या उनके क्षेत्र के भीतर व्यक्तियों द्वारा सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे व्यक्तियों के फायदा न तो ये और न कोई अन्य निधि, वित्तीय संपत्तियों या आर्थिक संसाधन उपलब्ध हों।
13. निर्णय किया गया है कि पैरा 12 द्वारा अधिरोपित निवारक उपाय संगत सदस्य राष्ट्रों द्वारा निर्णित निधियों, अन्य वित्तीय संपत्तियों या आर्थिक संसाधनों पर लागू नहीं होते:

(क)° संबंधित राष्ट्रों द्वारा समिति को यथोचित मामलों में ऐसे कोषों, अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों या आर्थिक संसाधनों तक पहुंच के लिए प्राधिकार देने के आशय की अधिसूचना समिति को देने और ऐसी अधिसूचना के बाद आधारभूत खर्चों के लिए आवश्यक राशि, खाद्य सामग्री के लिए भुगतान, किराया या गिरवी, दवाईयां और चिकित्सीय इलाज, कर, बीमा प्रीमियम और सार्वजनिक उपयोगिता प्रभार या केवल उचित व्यावसायिक फीस के भुगतान और राष्ट्रीय विधियों के अनुरूप विधिक सेवाओं के उपाबंधों से

संबद्ध खर्चों की वापसी, राष्ट्रीय विधि अनुसार शुल्क व सेवा प्रभार नेमी कार्य हेतु या कीलित निधियों, अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों और आर्थिक संसाधनों के अनुरक्षण; संबंधित राष्ट्रों द्वारा समिति को यथोचित मामलों में ऐसे कोषों, अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों या आर्थिक संसाधनों तक पहुंच के लिए प्राधिकार देना और ऐसी अधिसूचना के पांच दिन के भीतर समिति द्वारा नकारात्मक निर्णय नहीं लेना;

(ख)° असाधारण खर्चों के लिए आवश्यक राशि, बशर्ते कि ऐसे निर्णय को संगत राष्ट्र या सदस्य राष्ट्रों द्वारा समिति को अधिसूचित किया गया हो और समिति ने इसे अनुमोदित कर दिया हो;

(ग)° न्यायिक, प्रशासनिक या माध्यस्थन संबंधी ग्रहणाधिकार के अध्याधीन या निर्णय का विषय हो, निधियों, अन्य वित्तीय संपत्तियों और आर्थिक संसाधनों, जिसका उपयोग उस ग्रहणाधिकार या निर्णय का समाधान करने के लिए किया जाए बशर्ते कि वह संबंध या निर्णय वर्तमान संकल्प की तारीख से पूर्व किया गया हो, समिति द्वारा नामोदिष्ट व्यक्ति के लाभार्थ न हो और संगत राष्ट्रों या सदस्य राष्ट्रों द्वारा समिति को अधिसूचित हो।

14° निर्णय किया गया है कि सदस्य राष्ट्र पैरा 12 के उपाबंधों के अनुसरण में कीलित (फ्रोजन) खातों में अर्जित ब्याज या अन्य आय या करारों, संविदों या बाध्यताओं के अंतर्गत देय भुगतान जो कि उस तिथि से पूर्व प्राप्त हुए जब ये खाते इस संकल्प के प्रावधानों के अध्याधीन बने, बशर्ते कि ऐसा ब्याज, अन्य अर्जित आय और भुगतान इन प्रावधानों के अध्याधीन हों और कीलित (फ्रोजन) किए गए हों।

15° निर्णय किया गया है कि उपर्युक्त पैरा 12 में दिए गए निवारक उपाय/नामोदिष्ट व्यक्ति को सूचीबद्ध करने से पूर्व किए गए करार के अंतर्गत देय भुगतान से नहीं रोकेगा बशर्ते कि संगत राष्ट्र ने यह निर्णय किया है कि यह भुगतान उपर्युक्त पैरा 12 के अनुसरण में सीधे तौर पर या अप्रत्यक्ष रूप से नामोदिष्ट व्यक्ति द्वारा प्राप्त नहीं किया जा रहा है और संबंधित राष्ट्रों द्वारा समिति को ऐसे भुगतान करने या प्राप्त करने या यथोचित मामले में प्राधिकृत करने, इस प्रयोजन से निधियों, अन्य वित्तीय संपत्तियों या आर्थिक संसाधनों का कीलन समाप्त करने की अधिसूचना ऐसे प्राधिकरण के दस दिन पूर्व की गई हो।

मंजूरी समिति/विशेषज्ञों का पैनल

16. निर्णय किया गया है कि प्रक्रिया के अंतिम नियमों के नियम 28 के अनुसार, परिषद के सभी सदस्यों वाली सुरक्षा परिषद की समिति (यहां से समिति कहा गया है) को निम्नलिखित कार्य करने हैं:-

(क)° इस संकल्प के पैरा 9 और 12 द्वारा किए गए उपायों के कार्यान्वयन की निगरानी करना ताकि सदस्य राष्ट्रों द्वारा इन उपायों को सुदृढ़ करने, सुविधा प्रदान करने या कार्यान्वयन में सुधार किया जा सके;

(ख)° उपर्युक्त पैरा 6 और 7 में उल्लिखित कृत्यों में शामिल हो सकने वाले उन व्यक्तियों और निकायों के बारे में जानना और सूचना का पुनरावलोकन करना;

(ग)° उपर्युक्त पैरा 9 द्वारा किए गए उपायों के अध्याधीन व्यष्टिकों को अभिहित करना और उपर्युक्त पैरा 11 के अनुसार छूट के ले अनुरोधों पर विचार करना;

(घ)° उपर्युक्त पैरा 12 द्वारा किए गए उपायों के अध्याधीन व्यक्तियों और निकायों को अभिहित करना और उपर्युक्त पैरा 13 के अनुसार छूट के लिए अनुरोधों पर विचार करना;

(ङ)° उपर्युक्त अधिरोपित किए गए उपायों के कार्यान्वयन को सुकर बनाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देशों को तैयार करना;

(च)° अपने कार्य के बारे में सुरक्षा परिषद को 60 दिन के भीतर रिपोर्ट करना और इसके उपरान्त समिति द्वारा आवश्यक समझी गई अवधि में रिपोर्ट करना;

(छ)° समिति और हितबद्ध सदस्य राष्ट्रों, विशेषकर उस क्षेत्र को वार्ता के लिए प्रोत्साहित करना और साथ ही उपायों के कार्यान्वयन पर विचार-विमर्श करने के लिए समिति से मिलने के लिए ऐसे राज्यों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित करना;

(ज)° अधिरोपित उपायों को उनके द्वारा प्रभावशाली तरीके से कार्यान्वित करने के लिए की गई कार्रवाई के बारे में सभी राज्यों से जो भी सूचना उपयोगी है उसे प्राप्त करना; और

(झ)° इस संकल्प में अंतर्विष्ट उपायों के तथाकथित उल्लंघन या अनुपालन न करने के बारे में सूचना की जांच करना और समुचित कार्रवाई करना;

17. इस संकल्प के पैरा 9 तथा 12 को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में इस संकल्प के पारित होने के नब्बे दिन के भीतर समिति को रिपोर्ट देने के लिए सभी सदस्य राज्यों का आह्वान करना।

18. महासचिव को इस संकल्प के पारित होने की तरह महीने की प्रारंभिक अवधि के लिए समिति के निर्देशों के अनुसार अधिकतम पांच विशेषज्ञों (विशेषज्ञों का पैनल) का एक समूह गठित करने का अनुरोध करना और इस पैनल के कार्यों का समर्थन करने के लिए आवश्यक वित्तीय तथा सुरक्षा प्रबंध करना, 2 मार्च, 2016 तक इस अधिदेश के नवीकरण पर विचार करने का आशय व्यक्त करना तथा निर्णय लेना कि पैनल निम्नलिखित कार्य करेगा:

(क) इस संकल्प में विनिर्दिष्ट अधिदेशों को पूरा करने में समिति की सहायता करना और उपर्युक्त पैरा 6 तथा 7 में वर्णित कार्यों में शामिल व्यष्टिकों और इकाई के संभावित नामनिर्देश से संबंधित जानकारी से समिति को अवगत कराना;

(ख) इस संकल्प में निर्णीत उपायों के कार्यान्वयन से संबंधित जानकारी एकत्रित करना, जांच करना और विश्लेषण करना, विशेषकर गैर-अनुपालन की स्थिति में नीचे दिए गए पैरा 21 और 22 में उल्लिखित निर्धारण पर विशेष ध्यान देते हुए;

(ग) अवैध व्यापार के नेटवर्क सहित अंतिम शांति करार निष्पन्न करने की राजनीतिक प्रक्रिया को क्षति पहुंचाने वाले अथवा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून या अंतर्राष्ट्रीय मानवीय विधि का उल्लंघन करने वाले, जो लागू हो, को शस्त्रों तथा संबंधित सामग्री एवं संबंधित सैन्य या अन्य सहायता के बारे में जानकारी एकत्रित करना, उसकी जांच और विश्लेषण करना;

(घ) समिति के साथ चर्चा के बाद परिषद को 1 सितंबर, 2015 तक एक अंतरिम रिपोर्ट और 1 फरवरी, 2016 तक एक अंतिम रिपोर्ट प्रदान करना तथा जिन महीनों में ये रिपोर्ट देय हैं उसके सिवाए प्रत्येक महीने अद्यतन स्थिति प्रदान करना; तथा

(ङ) इस संकल्प में अधिरोपित उपायों के अध्यधीन व्यष्टिकों तथा असितत्वों की सूची पर जानकारी को संशोधित व अद्यतित करने में समिति की सहायता करना और साथ ही सूचीकरण के कारणों के बारे में आम जनता में फैली हुई कहानियों के बारे में सूचना एवं अतिरिक्त सूचना जुटाने का उपाबंध करना।

19. विशेषज्ञों के पैनल के साथ सहयोग सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय संगठनों सहित सभी पक्षकारों और सभी सदस्य राज्यों से अनुरोध करना तथा सभी शामिल सदस्य राष्ट्रों से यह भी अनुरोध करना कि विशेषज्ञों के पैनल के सदस्यों की सुरक्षा सुनिश्चित जांच तथा विशेषज्ञों के पैनल के आदेश में उल्लिखित व्यक्तियों दस्तावेजों तथा स्थलों तक उनकी निर्बाध पहुंच हो ताकि अधिदेश को कार्यान्वित किया जाए।

20. संकल्प 1998(2011) के पैरा 9 तथा संकल्प 1960 के पैरा 7 में बालकों एवं सशस्त्र संघर्ष के महासचिव के विशेष प्रतिनिधि तथा संघर्ष के दौरान हिंसा संबंधी विशेष प्रतिनिधि से समिति के साथ जानकारी साझा करने के लिए अनुरोध करना।

पुनर्विलोकन

21. आईजीएडी द्वारा 5 मार्च, 2015 तक की यथासम्मत अंतिम समय-सीमा के भीतर और पुनः 1 अप्रैल, 2015 को पारगमन-पूर्व अवधि की विचारित शुरुआत और तत्पश्चात 60 दिन या उससे पूर्व, जैसी आवश्यकता हो, स्थिति का पुनर्विलोकन करने का आशय व्यक्त करती है तथा साथ ही अभिव्यक्त के संदर्भ में अनुक्रिया करने के लिए तत्समय उचित समझे जाने वाला कोई पाबंदी लगाने की भी इच्छा व्यक्त करती है जिसमें सैन्य प्रतिबंध लगाना और दक्षिण सूडान की शांति, सुरक्षा और स्थिरता को चुनौती देने वाले कार्यों और नीतियों के लिए उत्तरदायी वरिष्ठ व्यक्तियों को नामित करना शामिल हो सकता है, ताकि दक्षिण सूडान की सरकार तथा विपक्षी बलों को राष्ट्रीय एकता पर आधारित संक्रमणकालीन सरकार का गठन करने, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रणाधीन सेनाओं को सैन्य अभियान, हिंसापूर्ण कार्यों के साथ-साथ मानवाधिकारों का उल्लंघन रोकने के लिए व्यापक व कारगर उपाय करने हेतु प्रोत्साहित किया जा सके तथा मानवीय सहायता को पूर्णतः सुलभ बनाया जा सके।

22. यह भी पुष्टि करती है कि इसे इस संकल्प में अंतर्विष्ट उपायों को समायोजित करने के लिए तैयार किया जाएगा और साथ ही अतिरिक्त उपायों को सुदृढ़ करने के साथ-साथ उपांतरण, शांति, उत्तरदायित्व तथा मेल-मिलाप की प्रक्रिया के संबंध में हुई प्रगति के आलोक में तथा साथ ही पक्षकारों की प्रतिबद्धताओं के कार्यान्वयन के आलोक में और साथ ही शत्रुतापूर्ण करारों पर विराम लगाने तथा इस संकल्प की प्रस्तावना में विनिर्दिष्ट अन्य प्रतिबद्धताओं और इस संकल्प के अनुपालन के आलोक में निवारक उपायों के निलंबन या उन्हें हटाने की कार्रवाई की जाएगी।

23. इस मामले पर अपना अभिग्रहण विधिक बनाए रखने का निर्णय करती है।

2206 संस्वीकृत सूची अंतिम बार अद्यतित की गई: 01 जुलाई, 2015

2206 समिति द्वारा

तैयार और अनुरक्षित सूची

प्रारंभन तारीख: 01 जुलाई, 2015

सूची संघटक

इस सूची में नीचे विनिर्दिष्ट दो खंड;

.क° व्यष्टिक

.ख° निकाय और अन्य समूह

गैर-सूचीबद्ध के बारे में समिति के निम्नलिखित वेबसाइट पर सूचना प्राप्त की जा सकती है:

<http://www.un.org/sc/committees/dfp.shtml>.

.क° व्यष्टिक

एसएसआई.°003 नाम: 1. जेम्स 2.कोआंग 3. चौल 4.उपलब्ध नहीं।

उपाधि: मेजर जनरल पदनाम: उपलब्ध नहीं, जन्मतिथि: 1961, जन्मस्थान: उपलब्ध नहीं, पहचान हेतु पर्याप्त उर्फ (क) जेम्स कोआंग चौल रेनले (ख) जेम्स कोआंग चौल (ग) कोआंग चौल रेनले (घ) जेम्स कोआंग चौल, पहचान हेतु अपर्याप्त उर्फ: उपलब्ध नहीं। राष्ट्रिकता: दक्षिण सूडान, पासपोर्ट सं. आर00012098, दक्षिण सूडान, राष्ट्रीय पहचान सं. उपलब्ध नहीं, पता: उपलब्ध नहीं, सूचीबद्ध: 1 जुलाई 2015, अन्य जानकारी: दिसंबर, 2014 में सूडान पीपल्स लिबरेशन आर्मी (एसपीएलएआईओ) विशेष प्रभाग के कमांडर नियुक्त हुए। उनके दल नागरिकों के विरुद्ध हमलों में शामिल रहे हैं। फरवरी, 2014 में उनके कमांड में दलों ने संयुक्त राष्ट्र कैपों, अस्पतालों, चर्चों तथा स्कूलों पर हमला किया, सरकार के साथ जुड़े पुलिस कर्मियों, सैनिकों तथा नागरिकों को तबाह करने के प्रयास, बड़े पैमाने, बलात्संग, उत्पीड़न तथा संपत्ति के विनाश में शामिल हैं।

एसएसआई.°002 नाम: 1. सिमोन 2. गेट्वेक 3. ड्यूअल 4.उपलब्ध नहीं।

उपाधि: मेजर जनरल पदनाम: चीफ आफ जनरल स्टाफ, विपक्ष में एसपीएलए जन्मतिथि: 1953 जन्मस्थान (क) अकेबो, जोंगली राज्य, सूडान/दक्षिण सूडान (ख) उरोर काउंटी, जोंगली राज्य, सूडान/दक्षिण सूडान, पहचान हेतु पर्याप्त उर्फ (क) सिमोन गेट्वेक ड्यूअल (ख) सिमोन गेट्वेक ड्यूअल (ग) सिमोन गेट्वेक ड्यूअल (घ) सिमोन गेट्वेक (ड.) सिमोन गेट्वेक (च) सिमोन गेट्वेक (छ) सिमोन गारविच पहचान हेतु अपर्याप्त (क) जनरल गेट्वेक (ख) धुअल राष्ट्रिकता: उपलब्ध नहीं, पासपोर्ट सं. उपलब्ध नहीं, राष्ट्रीय पहचान सं. उपलब्ध नहीं, पता: जोंगली राज्य सूडान/दक्षिण सूडान, सूचीबद्ध: 1 जुलाई, 2015 अन्य जानकारी: एसपीएलएमआईओ के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ है तथा पहले जोंगली राज्य में विपक्षी दलों के कमांडर थे। फरवरी 2015 से पहले इनके दलों ने जोंगली राज्य में हमले किए थे और मार्च, 2015 तक इन्होंने सिविलियन जनसंख्या पर हमलों के माध्यम से जोंगली राज्य की शांति भंग करने की कोशिश की थी।

एसएसआई.°006 नाम: 1. पीटर 2.गेडेट 3. उपलब्ध नहीं 4.उपलब्ध नहीं।

उपाधि: (क) जनरल (ख) मेजर जनरल, पदनाम: उपलब्ध नहीं, जन्मतिथि: 1957 तथा 1959 के बीच, जन्मस्थान (क) मयोम काउंटी यूनिटि स्टेट (ख) मेयन, यूनिटि स्टेट, पहचान हेतु पर्याप्त उर्फ (क) पीटर गेडेट याका (ख) पीटर गेडेट याक (ग) पीटर गेडेट याक (घ) पीटर गेडेट याक (ङ) पीटर गेडेट (च) पीटर गेडीट याका, पहचान हेतु: पर्याप्त उपलब्ध नहीं, राष्ट्रिकता: उपलब्ध नहीं, पासपोर्ट सं. उपलब्ध नहीं, राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं, पता: उपलब्ध नहीं, सूचीबद्ध: 1 जुलाई, 2015, अन्य जानकारी: 21 दिसंबर, 2014 को, ऑपरेशन्स के लिए एसपीएलए-आईओ के डिप्टी चीफ ऑफ स्टॉफ नियुक्त किए गए थे। उनके कमांड में दलों ने स्त्रियों सहित नागरिकों पर लक्ष्य किया, अप्रैल, 2014 में बेटियु पर हमले के दौरान जातीयता के आधार पर हत्याएं की।

एसएसआई.001 नाम: 1. गेब्रियल 2. जोक रिआक 3. उपलब्ध नहीं 4. उपलब्ध नहीं।

उपाधि: ल्यूटिनेंट जनरल पदनाम: सूडान पीपल्स लिबरेशन आर्मीज (एसपीएलए) क्षेत्र एक कमांडर, जन्मतिथि: 1966, जन्मस्थान: बोर, सूडान/दक्षिण सूडान, पहचान हेतु पर्याप्त उर्फ (क) गैब्रियल जोक (ख) जोक रिआक (ग) जोक रिआक, पहचान हेतु अपर्याप्त उर्फ उपलब्ध नहीं, राष्ट्रिकता: दक्षिण सूडान, पासपोर्ट सं. उपलब्ध नहीं, राष्ट्रीय पहचान सं. उपलब्ध नहीं, पता: (क) यूनिटी स्टेट, दक्षिण सूडान (ख) वाउ वेस्टर्न बहर अल गजल, दक्षिण सूडान, सूचीबद्ध: 1 जुलाई, 2015, अन्य जानकारी: एसपीएलए क्षेत्र एक की कमांड की, जो प्रारंभिक रूप से जनवरी, 2013 से यूनिटी स्टेट के अंदर संचालित था। एसपीएलए क्षेत्र एक कमांडर के रूप में उन्होंने दक्षिण सूडान में युद्धविराम करार के उल्लंघन के माध्यम से विरोध को बढ़ावा दिया एवं फैलाया। एसपीएलए एक दक्षिण सूडानी सैन्य सत्ता है जो दक्षिण सूडान में विरोध को बढ़ावा दे रही है जिसमें जनवरी, 2014 के युद्ध विराम करार और 9 मई, 2014 को दक्षिण अफ्रीका में संकट को सुलझाने हेतु करार, जो सीओएचए की एक पुनः प्रतिबद्धता थी का उल्लंघन शामिल है तथा इन्होंने आईजीएडी की निगरानी एवं सत्यापन तंत्र के कार्यकलापों को प्रतिबंधित किया।

एसएसआई.005 नाम: 1. मरिअल 2. चौंग 3. योल 4. मंगोक।

उपाधि: उपलब्ध नहीं, पदनाम: (क) सूडान पीपल्स लिबरेशन आर्मी मेजर जनरल (ख) कमांडर, प्रेसिडेंशियल गार्ड यूनिट, जन्मतिथि: 1 जनवरी, 1960 जन्मस्थान: यिरोल, लेक्स स्टेट पहचान हेतु पर्याप्त उर्फ (क) मेरिअल चिनींग (ख) मेरिअल चैन (ग) मेरिअल चनौंग योल (घ) मेरिअल चिनींग, पहचान हेतु अपर्याप्त उर्फ: उपलब्ध नहीं, राष्ट्रीयता: दक्षिण सूडान, पासपोर्ट सं. आर00005943 दक्षिण सूडान राष्ट्रीय पहचान सं. उपलब्ध नहीं, पता: उपलब्ध नहीं, सूचीबद्ध: 1 जुलाई, 2015, अन्य जानकारी: राष्ट्रपति के गार्ड ने जुबा के निकट नुवेर नागरिकों की हत्या कर दी और उनमें कईयों को कब्रों में दफना दिया। उसमें एक ऐसी भी कब्र थी जिसमें 200-300 सिविलियन थे।

एसएसआई.004 नाम: 1. सेंटिनो 2. डेंग 3. वोल 4. उपलब्ध नहीं।

उपाधि: मेजर जनरल पदनाम: एस पी एल ए के तीसरे प्रभाग के कमांडर, जन्मतिथि: 9 नवंबर, 1962, जन्मस्थान- एवील, सूडान/दक्षिण सूडान, पहचान हेतु पर्याप्त उर्फ (क) सेंटिनो डेंग बोल (ख) सेंटिनो डेंग कौल, पहचान हेतु अपर्याप्त उर्फ: उपलब्ध नहीं, राष्ट्रीयता: उपलब्ध नहीं, पासपोर्ट सं. उपलब्ध नहीं, राष्ट्रीय पहचान सं. उपलब्ध नहीं, पता: उपलब्ध नहीं, सूचीबद्ध: 1 जुलाई, 2015, अन्य जानकारी: विपक्षी दलों के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई का निदेश दिया और नेतृत्व किया तथा सीओएचए के उल्लंघन में संघर्षपूर्ण सैन्य अभियान चलाया। 2015 के दौरान इसकी कमांड में दलों ने बालकों, महिलाओं एवं बुजुर्ग आदमियों की हत्या की तथा जैसे-जैसे वे यूनिटी स्टेट से थोरजथ तेल क्षेत्र की ओर बढ़े पशुधन की चोरी की थी।

(ख) अस्तित्व और अन्य समूह

[फा. सं. यू-11/152/21/2015]

रुदेन्द्र टंडन, संयुक्त सचिव (यूएनपी)

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

ORDER

New Delhi, the 5th May, 2016

S.O. 1669(E).—Whereas the Security Council of the United Nations in its 7396th Meeting adopted Resolution 2206 (2015) (appended to this Order), under Chapter VII of the Charter of the United Nations requiring all states to take

measures to ensure that any funds, financial assets or economic resources are prevented from being made available by their nationals or by any individuals or entities within their territories, to or for the benefit of the individuals or entities designated by the Committee established by the said Resolution and to prevent the entry into or transit through its territories of designated individuals;

And whereas, the Central Government considers it necessary and expedient to issue an order under the United Nations (Security Council) Act, 1947 (43 of 1947) to implement the said Resolution of the Security Council adopted under Chapter VII of the Charter of the United Nations in order to support the search for an inclusive and sustainable peace in South Sudan;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 2 of the United Nations (Security Council) Act, 1947 (43 of 1947), the Central Government hereby makes the following Order to give effect to the said Resolution, namely:-

1. Short title and commencement- (1) This order may be called the Implementation of United Nations Security Council Resolution on South Sudan Order, 2016.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. Definitions- (1) In this order, unless the context otherwise requires, -

(a) "Committee" means the Sanctions Committee established by the Security Council of the United Nations in accordance with paragraph 16 of the Resolution 2206 (2015).

(b) "Resolution" means the Resolution 2206 (2015) of the Security Council of the United Nations adopted on 03 March 2015 and includes Resolutions 2057 (2012), 2109 (2013), 2132 (2013), 2155 (2014) and 2187 (2014) adopted by the Security Council under Chapter VII of the Charter of the United Nations on South Sudan;

(c) "Schedule" means the Schedule annexed to this Order, drawn on the basis of the determination made by the Security Council in their said Resolutions.

(2) Words and expressions used but not defined in this order and defined in any other law for the time being in force shall have the same meaning respectively assigned to them in such laws.

3. Application of Order- The provisions of this Order, as amended from time to time, shall apply to individuals and entities falling within the purview of the said Resolutions and the Schedule.

4. Powers of the Central Government to give effect to the Resolution- The Central Government shall have all the powers to take measures to,

(a) freeze without delay all funds, other financial assets and economic resources which are on its territories, and owned or controlled, directly or indirectly, by any individual or entity that may be designated by the Committee, or by any individual or entity acting on their behalf or at their direction, or by entities owned or controlled by them,

(b) ensure that neither these nor any other funds, financial assets or economic resources specified in clause (a) nor any other funds, financial assets or economic resources are made available, directly or indirectly for such persons' benefit, by their nationals or by persons within their territory with the provision to exempt the;

(i) basic expenses;

(ii) extraordinary expenses; and

(iii) expenses related to judicial, administrative or arbitral lien or judgement,

subject to the procedures specified in paragraph 13 and paragraphs 14 and 15 of the Resolution 2206 (2015) as may be applicable in the instant case;

(c) prevent the entry into or transit through its territories of designated individuals with the provision to exempt travel or entry or transit,

(i) justified on the grounds of humanitarian needs, including religious obligation as determined by the Committee on a case by case basis,

(ii) for the fulfilment of a judicial process, and

(iii) to further the objectives of peace and national reconciliation in South Sudan as determined by the Committee on a case-by-case basis;

subject to the procedures specified in paragraph 11 of the Resolution 2206 (2015), as may be applicable in the instant case.

Schedule

[See paragraph 2 (b)]

This Schedule includes the followings namely:-

- I. Text of UNSC Resolution 2206 (2015) adopted by the United Nations Security Council on 3 March 2015;
- II. The list established and maintained by the 2206 Committee.

I. United Nations Security Council Resolution S/RES/2206 (2015)

Adopted by the Security Council at its 7396th meeting, on 3 March 2015

The Security Council,

Recalling its previous resolutions and statements on South Sudan, in particular resolutions 2057 (2012), 2109 (2013), 2132 (2013), 2155 (2014) and 2187 (2014),

Expressing grave alarm and concern regarding the conflict between the Government of the Republic of South Sudan and opposition forces since December 2013 which emanated from internal political disputes among the country's political and military leaders,

Deeply concerned that the conflict has resulted in great human suffering, including significant loss of life, displacement of two million people, and the loss of property, further impoverishing and disadvantaging the people of South Sudan,

Strongly condemning past and ongoing human rights violations and abuses and violations of international humanitarian law, including those involving targeted killings of civilians, ethnically-targeted violence, extrajudicial killings, rape, and other forms of sexual and gender-based violence, recruitment and use of children in armed conflict, abductions, enforced disappearances, arbitrary arrests and detention, violence aimed at spreading terror among the civilian population, and attacks on schools, places of worship and hospitals, as well as United Nations and associated peacekeeping personnel and objects, by all parties, including armed groups and national security forces, as well as the incitement to commit such abuses and violations, *further condemning* harassment and targeting of civil society, humanitarian personnel and journalists, and *emphasizing* that those responsible for violations of international humanitarian law and violations and abuses of human rights must be held accountable, and that the Government of South Sudan bears the primary responsibility to protect its population from genocide, war crimes, ethnic cleansing, and crimes against humanity,

Expressing deep concern over the large-scale displacement of persons and deepening humanitarian crisis, *stressing* the responsibility borne by all parties to the conflict for the suffering of the people of South Sudan, and the necessity of ensuring that the basic needs of the population are met, *commending* United Nations humanitarian agencies and partners for their efforts to provide urgent and coordinated support to the population, *calling upon* all parties to the conflict to allow and facilitate, in accordance with relevant provisions of international law and United Nations guiding principles of humanitarian assistance, the full, safe, and unhindered access of relief personnel, equipment and supplies to all those in need and the timely delivery of humanitarian assistance, in particular to internally displaced persons and refugees, *condemning* all attacks against humanitarian personnel and facilities and *recalling* that attacks against humanitarian personnel and depriving civilians of objects indispensable to their survival may amount to violations of international humanitarian law,

Commending the Intergovernmental Authority on Development (IGAD) Ministerial Group's initiative, as supported by the United Nations and African Union, in establishing a forum for political and security dialogue, and *expecting* all parties to participate in this process and respect the decisions reached by IGAD Assembly of Heads of State and Government on 13 March 2014,

Welcoming the IGAD-mediated commitments made to resolve the crisis in South Sudan, namely the 23 January 2014 Cessation of Hostilities Agreement; 9 May 2014 Agreement to Resolve the Crisis in South Sudan; and the 1 February 2015 Areas of Agreement of the Establishment of the Transitional Government of National Unity (TGoNU) in the Republic of South Sudan,

Welcoming the resolve indicated in the IGAD Assembly of Heads of State and Government Communiqué of 10 June 2014 and 25 August 2014 that IGAD Member States will take further collective action, including through the imposition of punitive measures, to pressure any party that fails to honour its commitments to date or acts contrary to the Communiqué of that Assembly,

Welcoming the Communiqué of the African Union Peace and Security Council (AU PSC) of 12 June 2014, which, inter alia, reiterated the readiness of that Council, upon recommendation by IGAD, to immediately pursue targeted sanctions and other measures against any party that continues to undermine the search for a solution to the conflict and fails to honour its commitments,

Welcoming further the Communiqué of the AU PSC of 17 September 2014 which, inter alia, reiterated its determination, in coordination with IGAD, to take the necessary measures against any party that fails to honour its commitments and continues to undermine the search for a negotiated solution to the current crisis,

Strongly condemning the Government of the Republic of South Sudan and the Sudan People's Liberation Movement (SPLM) —in Opposition for failing to reach agreement to form a transitional government within the 60-day period outlined in the 26th Communiqué of 10 June 2014,

Taking note of the Communiqué of the 27th Extraordinary Session of the IGAD Assembly of Heads of State and Government in Addis Ababa on 25 August 2014, which inter alia: deplored the numerous violations of the agreements signed by the Parties to date, reiterated the need for an inclusive and broad-based approach to negotiations; expressed serious concerns over the worsening humanitarian situation in South Sudan; and called upon the stakeholders to negotiate and complete the agreement on a Transitional Government of National Unity within 45 days,

Taking note of the Communiqué of the 28th Extraordinary Session of the IGAD Assembly of Heads of State and Government in Addis Ababa on 7 November 2014, which inter alia: resolved that the Government of South Sudan and opposition forces commit to an unconditional, complete and immediate end to all hostilities; invited collective action by the States of the IGAD region to enact asset freezes and travel bans within the region, and denied the supply of arms and ammunition and any other materiel that could be used in war if the Government of South Sudan and opposition forces commit any violation of the cessation of hostilities; and called on the AU PSC, the United Nations Security Council, and the international community to render all possible assistance in the implementation of these measures, should it be necessary to implement these measures,

Taking note of the 21 January 2015 Agreement on the Reunification of the SPLM, agreed under the aegis of the Government of the United Republic of Tanzania, and 16 February 2015 Communiqué of the Meeting of the SPLM Tripartite Committee on the Implementation of Phase I of the Arusha SPLM Reunification Agreement,

Taking note of the AU PSC Communiqués dated 5 December 2014 and 29 January 2015 which, inter alia, stressed that sanctions will be imposed against all parties that continue to obstruct the political process and undermine the Cessation of Hostilities Agreement of 23 January 2014,

Welcoming the China-mediated “Five-Point Plan” agreed upon by the representatives of the GRSS and the SPLM/A-in Opposition during the Special Consultation in Support of IGAD-led South Sudan Peace Process convened on 12 January in Khartoum, namely: (i) earnestly commit to the full implementation of all signed agreements; (ii) speed up the pace of negotiations towards the formation of a transitional government at an early date; (iii) take concrete steps to relieve the humanitarian situation in conflict-affected areas, and facilitate access of international humanitarian assistance; (iv) ensure the safety of all personnel and assets of all countries and international entities operating in South Sudan; and (v) provide strong support for and take active part in the IGAD-led mediation efforts, and, in this regard, *strongly urging* both parties to immediately implement the Five-Point Plan,

Expressing its deep appreciation for the actions taken by the United Nations Mission in South Sudan (UNMISS) peacekeepers and troop-and police-contributing countries to protect civilians, including foreign nationals, under threat of physical violence and to stabilize the security situation,

Recognizing the importance of independent and public human rights monitoring, investigation and reporting for its useful role in laying the groundwork for justice, accountability, reconciliation and healing among all South Sudanese communities,

Taking note with interest of the 21 February 2014 UNMISS Interim Human Rights report, and 8 May 2014 UNMISS “Conflict in South Sudan: A Human Rights Report,” and the 19 December 2014 UNMISS “Special Report: Attack on Bentiu, Unity State, 29 October 2014,” 29 October 2014 UNMISS “Special Report: Attack on Bentiu, Unity State” and the 9 January 2015 UNMISS Report on “Attacks on Civilians in Bentiu & Bor”,

Expressing grave concern that, according to the UNMISS 8 May 2014 “Conflict in South Sudan: A Human Rights Report” there are reasonable grounds to believe that crimes against humanity, including extrajudicial killings, rape and other acts of sexual violence, enforced disappearances, and arbitrary detention have been committed by both government and opposition forces, and that war crimes have been committed, and, stressing the urgent and imperative need to end impunity in South Sudan and to bring to justice perpetrators of such crimes,

Stressing the importance of accountability, reconciliation, and healing as prominent elements of a transitional agenda while taking note of the important role international investigations, and where appropriate, prosecutions can play with respect to holding those responsible for war crimes and crimes against humanity,

Recognizing the work of the African Union Commission of Inquiry (AU COI) in investigating and documenting violations as well as abuses of international human rights law and international humanitarian law in South Sudan, *anticipating with interest* its findings and recommendations, *encouraging* the public release of its final report as soon as possible, and *welcoming* the further engagement of the African Union to ensure justice and accountability, as well as healing and reconciliation for South Sudan,

Strongly condemning the use of media to broadcast hate speech and transmit messages instigating sexual violence against a particular ethnic group, which has the potential to play a significant role in promoting mass violence and exacerbating conflict, and *calling on* the Government of the Republic of South Sudan to take appropriate measures to address such activity, and further *urging* all parties to desist from these actions and instead contribute to promoting peace and reconciliation among the communities,

Recognizing the important role played by civil society organizations, faith leaders, women, and youth in South Sudan, *underscoring* the importance of their participation—along with the former SPLM detainees and other political parties—to finding a sustainable solution to the crisis in the country, and *concerned* by efforts by the government to limit such participation including by preventing individuals from travelling to join the talks and by increased restrictions of freedom of expression,

Reaffirming all its relevant resolutions on women, peace, and security, on children and armed conflict, and the protection of civilians in armed conflict, as well as resolutions 1502 (2003) on the protection of humanitarian and United Nations personnel, resolution 2150 (2014) on the Prevention and Fight against Genocide, and resolution 2151 (2014) on security sector reform,

Recalling resolutions 1209 (1998) and 2117 (2013) and *expressing grave concern* at the threat to peace and security in South Sudan arising from the illicit transfer, destabilizing accumulation and misuse of small arms and light weapons and *emphasizing* the importance of strengthening efforts to combat the illicit circulation of such weapons,

Expressing deep concern at persistent restrictions placed upon the movement and operations of UNMISS, *strongly condemning* the attacks by government and opposition forces and other groups on United Nations and IGAD personnel and facilities, the detentions and kidnappings of United Nations and associated personnel and *calling upon* the Government of South Sudan to complete its investigations of these attacks in a swift and thorough manner and to hold those responsible to account,

Determining that the situation in South Sudan continues to constitute a threat to international peace and security in the region,

Acting under Article 41 of Chapter VII of the Charter of the United Nations,

1. *Endorses* the Cessation of Hostilities Agreements (“CoH Agreements”) accepted and signed by the Government of the Republic of South Sudan and SPLM—in Opposition on 23 January 2014, 6 May 2014 and 9 May 2014;

2. *Expresses deep concern* at the failures of both parties to honour their commitments to date, to engage the peace process meaningfully toward political resolution of the crisis and to bring an end to the violence and, in particular, *condemns* the continued and flagrant violations of the CoH Agreements as documented by the IGAD Monitoring and Verification Mechanism;

3. *Demands* that the parties respect all aspects of the CoH Agreements and immediately implement the necessary modalities in accordance with the 9 May 2014 Agreement and other relevant Agreements, including the progressive withdrawal of foreign forces deployed in South Sudan since 15 December 2013, *calls upon* all parties to armed conflict in South Sudan to issue clear orders prohibiting all violations of international humanitarian law and human rights violations and abuses, and *underscores* the necessity for all parties to ensure immediate access to humanitarian agencies and further *demands* that the parties commit to finding a comprehensive agreement without further delay;

4. *Reiterates* that there is no military solution to the conflict;

Sanctions Designation Criteria

5. *Underscores* its willingness to impose targeted sanctions in order to support the search for an inclusive and sustainable peace in South Sudan;

6. *Decides* that the provisions of paragraph 9 shall apply to individuals, and that the provisions of paragraph 12 shall apply to individuals and entities, as designated for such measures by the Committee established pursuant to paragraph 16 of this resolution (“the Committee”) pursuant to paragraphs 16 (c) and 16 (d), respectively, as responsible for or complicit in, or having engaged in, directly or indirectly, actions or policies that threaten the peace, security or stability of South Sudan;

7. *Underscores* that such actions or policies as described in paragraph 6 above may include, but are not limited to:

(a) Actions or policies that have the purpose or effect of expanding or extending the conflict in South Sudan or obstructing reconciliation or peace talks or processes, including breaches of the Cessation of Hostilities Agreement;

(b) Actions or policies that threaten transitional agreements or undermine the political process in South Sudan;

(c) Planning, directing, or committing acts that violate applicable international human rights law or international humanitarian law, or acts that constitute human rights abuses, in South Sudan;

(d) The targeting of civilians, including women and children, through the commission of acts of violence (including killing, maiming, torture, or rape or other sexual violence), abduction, enforced disappearance, forced displacement, or attacks on schools, hospitals, religious sites, or locations where civilians are seeking refuge, or through conduct that would constitute a serious abuse or violation of human rights or a violation of international humanitarian law;

(e) The use or recruitment of children by armed groups or armed forces in the context of the armed conflict in South Sudan;

(f) The obstruction of the activities of international peacekeeping, diplomatic, or humanitarian missions in South Sudan, including IGAD’s Monitoring and Verification Mechanism or of the delivery or distribution of, or access to, humanitarian assistance;

(g) Attacks against United Nations missions, international security presences, or other peacekeeping operations, or humanitarian personnel; or

(h) Acting for or on behalf of, directly or indirectly, an individual or entity designated by the Committee;

8. *Decides* that the provisions of paragraphs 9 and 12 shall apply to individuals, as designated for such measures by the Committee who are leaders of any entity, including any South Sudanese government, opposition, militia, or other group, that has, or whose members have, engaged in any of the activities described in paragraphs 6 and 7 above;

Travel Ban

9. *Decides* that, for an initial period of one year from the date of adoption of this resolution, all Member States shall take the necessary measures to prevent the entry into or transit through their territories of any individuals who may be designated by the Committee, provided that nothing in this paragraph shall oblige a State to refuse its own nationals entry into its territory;

10. *Notes* that designated individuals may have multiple nationalities or passports, *expresses* its concern that travel between the two States of which a designated individual has nationality or a passport may undermine the objectives of the travel ban imposed in paragraph 9, and *requests* that the Panel of Experts established in paragraph 18 of this resolution (the “Panel of Experts”) report to the Committee information about such travel;

11. *Decides* that the measures imposed by paragraph 9 above shall not apply:

(a) Where the Committee determines on a case-by-case basis that such travel is justified on the grounds of humanitarian need, including religious obligation;

(b) Where entry or transit is necessary for the fulfilment of a judicial process;

(c) Where the Committee determines on a case-by-case basis that an exemption would further the objectives of peace and national reconciliation in South Sudan and stability in the region;

Asset Freeze

12. *Decides* that, for an initial period of one year from the date of adoption of this resolution, all Member States shall freeze without delay all funds, other financial assets and economic resources which are on their territories, which are owned or controlled, directly or indirectly, by any individuals or entities that may be designated by the Committee, or by any individuals or entities acting on their behalf or at their direction, or by entities owned or controlled by them, and *decides* further that all Member States shall for this initial period ensure that neither these nor any other funds, financial

assets or economic resources are made available, directly or indirectly for such persons' benefit, by their nationals or by persons within their territory;

13. *Decides* that the measures imposed by paragraph 12 above do not apply to funds, other financial assets or economic resources that have been determined by relevant Member States:

(a) To be necessary for basic expenses, including payment for foodstuffs, rent or mortgage, medicines and medical treatment, taxes, insurance premiums, and public utility charges or exclusively for payment of reasonable professional fees and reimbursement of incurred expenses associated with the provision of legal services in accordance with national laws, or fees or service charges, in accordance with national laws, for routine holding or maintenance of frozen funds, other financial assets and economic resources, after notification by the relevant State to the Committee of the intention to authorize, where appropriate, access to such funds, other financial assets or economic resources and in the absence of a negative decision by the Committee within five working days of such notification;

(b) To be necessary for extraordinary expenses, provided that such determination has been notified by the relevant State or Member States to the Committee and has been approved by the Committee;

(c) To be the subject of a judicial, administrative or arbitral lien or judgment, in which case the funds, other financial assets and economic resources may be used to satisfy that lien or judgment provided that the lien or judgment was entered into prior to the date of the present resolution, is not for the benefit of a person designated by the Committee, and has been notified by the relevant State or Member States to the Committee;

14. *Decides* that Member States may permit the addition to the accounts frozen pursuant to the provisions of paragraph 12 above of interest or other earnings due on those accounts or payments due under contracts, agreements or obligations that arose prior to the date on which those accounts became subject to the provisions of this resolution, provided that any such interest, other earnings and payments continue to be subject to these provisions and are frozen;

15. *Decides* that the measures in paragraph 12 above shall not prevent a designated person from making payment due under a contract entered into prior to the listing of such a person, provided that the relevant States have determined that the payment is not directly or indirectly received by a person designated pursuant to paragraph 12 above, and after notification by the relevant States to the Committee of the intention to make or receive such payments or to authorize, where appropriate, the unfreezing of funds, other financial assets or economic resources for this purpose, ten working days prior to such authorization.

Sanctions Committee/Panel of Experts

16. *Decides* to establish, in accordance with rule 28 of its provisional rules of procedure, a Committee of the Security Council consisting of all the members of the Council (herein "the Committee"), to undertake the following tasks:

(a) To monitor implementation of the measures imposed by paragraphs 9 and 12 of this resolution with a view to strengthening, facilitating and improving implementation of these measures by Member States;

(b) To seek and review information regarding those individuals and entities who may be engaging in the acts described in paragraphs 6 and 7 above;

(c) To designate individuals subject to the measures imposed by paragraph 9 above and to consider requests for exemptions in accordance with paragraph 11 above;

(d) To designate individuals and entities subject to the measures imposed by paragraph 12 above, and to consider requests for exemptions in paragraph 13 above;

(e) To establish such guidelines as may be necessary to facilitate the implementation of the measures imposed above;

(f) To report within 60 days to the Security Council on its work and thereafter to report as deemed necessary by the Committee;

(g) To encourage a dialogue between the Committee and interested Member States, in particular those in the region, including by inviting representatives of such States to meet with the Committee to discuss implementation of the measures;

(h) To seek from all States whatever information it may consider useful regarding the actions taken by them to implement effectively the measures imposed; and,

(i) To examine and take appropriate action on information regarding alleged violations or non-compliance with the measures contained in this resolution;

17. *Calls upon* all Member States to report to the Committee ninety days from the adoption of this resolution on the steps they have taken to implement effectively paragraphs 9 and 12 of this resolution;

18. *Requests* the Secretary-General to create for an initial period, thirteen months from the adoption of this resolution, in consultation with the Committee, a group of up to five experts (“Panel of Experts”), under the direction of the Committee, and to make the necessary financial and security arrangements to support the work of the Panel, *expresses* its intent to consider the renewal of this mandate no later than March 2, 2016, and *decides* that the Panel shall carry out the following tasks:

(a) Assist the Committee in carrying out its mandate as specified in this resolution, including through providing the Committee with information relevant to the potential designation of individuals and entities who may be engaging in the activities described in paragraphs 6 and 7 above;

(b) Gather, examine and analyse information regarding the implementation of the measures decided in this resolution, in particular incidents of non-compliance, with particular focus on the benchmarks outlined in paragraphs 21 and 22 below;

(c) Gather, examine and analyse information regarding the supply, sale or transfer of arms and related materiel and related military or other assistance, including through illicit trafficking networks, to individuals and entities undermining political processes to reach a final peace agreement or participating in acts that violate international human rights law or international humanitarian law, as applicable;

(d) Provide to the Council, after discussion with the Committee, an interim report by September 1, 2015, a final report by February 1, 2016, and except in the months when these reports are due, updates each month; and,

(e) Assist the Committee in refining and updating information on the list of individuals and entities subject to the measures imposed by this resolution, including through the provision of identifying information and additional information for the publicly-available narrative summary of reasons for listing;

19. *Urges* all parties and all Member States, as well as international, regional and subregional organizations to ensure cooperation with the Panel of Experts and *further urges* all Member States involved to ensure the safety of the members of the Panel of Experts and unhindered access, in particular to persons, documents and sites in order for the Panel of Experts to execute its mandate;

20. *Requests* the Special Representative of the Secretary-General for Children and Armed Conflict and the Special Representative for Sexual Violence in Conflict to share relevant information with the Committee in accordance with paragraph 7 of resolution 1960 (2010) and paragraph 9 of resolution 1998 (2011);

Review

21. *Expresses* its intent to review the situation after the IGAD-agreed deadline of March 5, 2015, and again after the envisioned start of the Pre-Transition Period on April 1, 2015, and at 60-day intervals thereafter or more frequently, as needed, and also expresses its intent to impose any sanctions that may then be appropriate to respond to the situation, which may include an arms embargo and the designation of senior individuals responsible for actions or policies that threaten the peace, security or stability of South Sudan, so as to encourage the Government of South Sudan and opposition forces to form a transitional government of national unity, take effective and comprehensive steps to cause forces under direct or indirect control to cease military operations, acts of violence, as well as violations of human rights, and enable full access for humanitarian assistance;

22. *Affirms* also that it shall be prepared to adjust the measures contained in this resolution, including by strengthening through additional measures, as well as modification, suspension or lifting of the measures, as may be needed at any time in light of the progress achieved in the peace, accountability, and reconciliation process, and in light of the implementation of the parties’ commitments, including the Cessation of Hostilities Agreement and other commitments specified in the preamble of this resolution, and compliance with this resolution;

23. *Decides* to remain seized of the matter.

2206 Sanctions List Last updated on: 1 July 2015

**The List established and maintained
by the 2206 Committee**

Generated on: 1 July 2015

Composition of the List

The list consists of the two sections specified below:

A. Individuals

B. Entities and other groups

Information about de-listing may be found on the Committee's website at:

<http://www.un.org/sc/committees/dfp.shtml>.

A. Individuals

SSi.003 Name: 1: JAMES 2: KOANG 3: CHUOL 4: na

Title: Major General **Designation:** na **DOB:** 1961 **POB:** na **Good quality a.k.a.:** a) James Koang Chol Ranley b) James Koang Chol c) Koang Chuol Ranley d) James Koang Chual **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** South Sudan **Passport no:** R00012098, South Sudan **National identification no:** na **Address:** na **Listed on:** 1 Jul. 2015 **Other information:** Appointed commander of the Sudan People's Liberation Army in Opposition (SPLAIO) Special Division in December 2014. His forces have been engaged in attacks against civilians. In February 2014, forces under his command attacked United Nations camps, hospitals, churches, and schools, engaging in widespread rape, torture, and the destruction of property, in an attempt to flush out civilians, soldiers, and policemen allied with the government.

SSi.002 Name: 1: SIMON 2: GATWECH 3: DUAL 4: na

Title: Major General **Designation:** Chief of General Staff, SPLA in Opposition **DOB:** 1953 **POB:** a) Akobo, Jonglei State, Sudan/South Sudan b) Uror County, Jonglei State, Sudan/South Sudan **Good quality a.k.a.:** a) Simon Gatwich Dual b) Simon Getwech Dual c) Simon Gatwec Dual d) Simon Gatweach e) Simon Gatwick f) Simon Gatwech g) Simon Garwich **Low quality a.k.a.:** a) General Gaduel b) Dhual **Nationality:** na **Passport no:** na **National identification no:** na **Address:** Jonglei State, Sudan/South Sudan **Listed on:** 1 Jul. 2015 **Other information:** Is the SPLM-IO Chief of General Staff and was previously the commander of opposition forces in Jonglei State. His forces conducted an early February 2015 attack in Jonglei State, and as of March 2015, he had tried to destroy the peace in Jonglei State through attacks on the civilian population.

SSi.006 Name: 1: PETER 2: GADET 3: na 4: na

Title: a) General b) Major General **Designation:** na **DOB:** Between 1957 and 1959 **POB:** a) Mayom County Unity State b) Mayan, Unity State **Good quality a.k.a.:** a) Peter Gatdet Yaka b) Peter Gadet Yak c) Peter Gadet Yaak d) Peter Gatdet Yaak e) Peter Gatdet f) Peter Gatdeet Yaka **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** na **Passport no:** na **National identification no:** na **Address:** na **Listed on:** 1 Jul. 2015 **Other information:** Appointed the SPLA-IO's Deputy Chief of Staff for Operations on December 21, 2014. Forces under his command targeted civilians, including women, in April 2014 during an assault on Bentiu, including targeted killings on the basis of ethnicity.

SSi.001 Name: 1: GABRIEL 2: JOK RIAK 3: na 4: na

Title: Lieutenant General **Designation:** Sudan People's Liberation Army's (SPLA) Sector One Commander **DOB:** 1966 **POB:** Bor, Sudan/South Sudan **Good quality a.k.a.:** a) Gabriel Jok b) Jok Riak c) Jock Riak **Low quality**

a.k.a.: na **Nationality:** South Sudan **Passport no:** na **National identification no:** na **Address:** a) Unity State, South Sudan b) Wau, Western Bahr El Ghazal, South Sudan **Listed on:** 1 Jul. 2015 **Other information:** Has commanded SPLA Sector One, which operates primarily within Unity State, since January 2013. In his position as the SPLA Sector One commander, he has expanded or extended the conflict in South Sudan through breaches of the Cessation of Hostilities Agreement. The SPLA is a South Sudanese military entity that has engaged in actions that have extended the conflict in South Sudan, including breaches of the January 2014 Cessation of Hostilities Agreement and the May 9, 2014 Agreement to Resolve the Crisis in South Sudan, which was a re-commitment to the CoHA and has obstructed the activities of IGAD's Monitoring and Verification Mechanism.

SSi.005 Name: 1: MARIAL 2: CHANUONG 3: YOL 4: MANGOK

Title: na **Designation:** a) Sudan People's Liberation Army Major General b) Commander, Presidential Guard Unit **DOB:** 1 Jan. 1960 **POB:** Yirol, Lakes State **Good quality a.k.a.:** a) Marial Chinuong b) Marial Chan c) Marial Chanoung Yol d) Marial Chinoum **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** South Sudan **Passport no:** R00005943, South Sudan **National identification no:** na **Address:** na **Listed on:** 1 Jul. 2015 **Other information:** His Presidential Guard

led the slaughter of Nuer civilians in and around Juba, many who were buried in mass graves. One such grave was purported to contain 200-300 civilians.

SSi.004 Name: 1: SANTINO 2: DENG 3: WOL 4: na

Title: Major General **Designation:** Commander of the SPLA's Third Division **DOB:** 9 Nov. 1962 **POB:** Aweil, Sudan/South Sudan **Good quality a.k.a.:** a) Santino Deng Wuol b) Santino Deng Kuol **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** na **Passport no:** na **National identification no:** na **Address:** na **Listed on:** 1 Jul. 2015 **Other information:** Has led and directed military actions against opposition forces and conducted confrontational troop movements in violation of the CoHA. During May 2015, forces under his command killed children, women and old men, burned property, and stole livestock as they advanced through Unity State towards Thorjath oil field.

B. Entities and other groups

[F. No. U.II/152/21/2015]

RUDRENDRA TANDON, Jt. Secy. (UNP)